



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

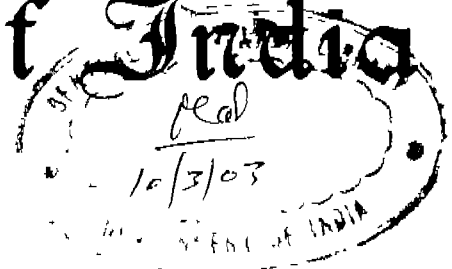
असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 227 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2002/भाद्र 7, 1924

No. 227]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2002/BHADRA 7, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2002

**विषय : चीन जनवादी गणराज्य तथा चीनी ताईपेई से प्लास्टिक ओपथालमिक लेंसों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।**

सं. 14/16/2002-डीजीएडी.— भारतीय प्लास्टिक ओपथालमिक लेंसेज एसोसिएशन (ईपोला), कर्नाटक का एक सदस्य मै. टेक्ट्रान पोलीलेसेज लिमिटेड, हैदराबाद ने घरेलू उद्योग की ओर से 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य तथा ताईवान (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से प्लास्टिक ओपथालमिक लेंसों के पाटन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है तथा इस संबंध में पाटनरोधी जांच तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। याचिका को इंडियन प्लास्टिक ओपथालमिक लेंसेज एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है जिनके अन्य सदस्य मै. टेक्ट्रान पोलीलेसेज लिमिटेड, हैदराबाद, मै. इंडियन ओपथालमिक लेंसेज मैन्यूफैक्चरिंग क.प्रा.लि., कर्नाटक तथा मै. प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (मद्रास) प्रा. लि., चेन्नई हैं।

1. **शामिल उत्पाद** वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्लास्टिक ओपथालमिक लेंस (जिसे इसमें इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) है तथा इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीमा शुल्क शीर्ष 9001.50) के अध्याय 90 के तहत वर्गीकृत किया गया है। प्लास्टिक ओपथालमिक लेंस का प्रयोग मानव जाति की दृष्टि को ठीक करने के लिए चश्मों में किया जाता है। ये बिना कटे लेंस चश्मों के ढांचे में चढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। ये लेंस बिना एलाइल डाई-कार्बोनेट जिसे सामान्यतः सी आर-39 जिसका अपवर्तनांक 1.498 तथा एबे सं 50 प्लस होता है, के रूप में जाना जाता है, से बने होते हैं।

इस उत्पाद का विनिर्माण मै. टेक्ट्रॉन पोलीलेसेज लि., हैदराबाद, मै. इंडियन ओपथालमिक लेंसेज मैन्यूफैक्चरिंग कं.प्रा.लि., कर्नाटक तथा मै. प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (मद्रास) प्रा.लि. चेन्नई द्वारा किया जाता है ।

वर्तमान जांच में सभी प्रकार के प्लास्टिक ओपथालमिक लेंस आते हैं । तथापि, वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र में बाध्यकारी नहीं हैं ।

2. **घरेलू उद्योग की स्थिति:** याचिका मै. टेक्ट्रॉन पोलीलेसेज लि., हैदराबाद ने दायर की हैं । मै. इंडियन प्लास्टिक ओपथालमिक लेंसेज एसोसिएशन (ईपोला) कर्नाटक द्वारा इसका समर्थन किया गया है जिसके सदस्य मै. टेक्ट्रॉन पोलीलेसेज लि., हैदराबाद मै. इंडियन ओपथालमिक लेंसेज मैन्यूफैक्चरिंग कं.प्रा.लि., कर्नाटक तथा मै. प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (मद्रास) प्रा.लि., चेन्नई हैं । याचिकाकर्ता इसलिए नियम 5(3)(क) तथा (ख) के अनुसार याचिका दायर करने की स्थिति में है और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है ।

3. **शामिल देश:** वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य तथा चीनी ताईपेई (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) हैं ।

4. **समान वस्तुएं** याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्सर्जित स्माटुएं संबद्ध देशों में उत्पादित वहां के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान हैं क्योंकि वे घरेलू वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकती हैं तथा जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है । तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं को नियम 2(घ) के आशय से संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समान समझा जा रहा है ।

5. **सामान्य मूल्य:** याचिकाकर्ताओं ने चीन पी आर तथा चीनी ताईपेई के लिए उचित रूप से समायोजित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन लागत के आंकड़े के आधार पर आधारित सामान्य मूल्य का दावा किया है जिस पर प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में यथा संशोधित पाटनरोधी नियमों के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य तथा चीनी ताईपेई में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के लिए विचार किया गया है ।

6. **निर्यात कीमत:** याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी तथा अनुपूरक स्रोत प्रमाणन सीमा शुल्क के आंकड़े के आधार पर 1999-2000, 2000-2001 तथा 1.4.2001 से 31.12.2002 तक की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य तथा चीनी ताईपेई में सी आई एफ कीमतों को प्रस्तुत किया है । प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रमाणित निर्यात कीमत के आधार पर कारखाना द्वार कीमत का निर्धारण किया है और कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़े तथा पत्तन खर्चों के लिए समायोजनों के साथ उचित तरीके से समायोजित किया है ।

7. **पाटन मार्जिन:** याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया है कि इस बात का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उस कीमत से अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

8. **क्षति तथा कारणात्मक संबंध:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से कथित पाटन आयातों में अत्याधिक वृद्धि तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु द्वारा कीमत कम हो जाने से याचिकाकर्ता बाजार में अपना हिस्सा नहीं बढ़ा सका जिससे प्रथम दृष्टया इस बात का संकेत मिलता है कि कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

9. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत:** उपरक्पात पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

10. **जांच की अवधि:** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक है।

11. **सूचना देना:** इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश/क्षेत्र के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग अलग लिखे जा रहे हैं कि वे निम्नलिखित पत्र पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं-

#### निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।

12. **समय सीमा** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पत्र पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

13. **अगोपनीय सारांश:** सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए पाटन रोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किसी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह सूचना नियम 7(1) तथा 7(2) के अनुसार स्वीकृति के अध्वधीन होगी।

14. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपान्तर रखे गए हैं।

15. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना नहीं देता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में पर्याप्त बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2002

**Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Plastic Ophthalmic Lenses from People's Republic of China and Chinese Taipei.**

**No. 14/16/2002-DGAD.**— M/s Techtran Polylenes Limited, Hyderabad, a member of Indian Plastic Ophthalmic Lenses Association (IPOLA), Karnataka has filed a petition on behalf of the Domestic Industry in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) alleging dumping of Plastic Ophthalmic Lenses from People's Republic of China and Chinese Taipei (herein after referred to as subject countries) and requested for anti dumping investigations and levy of anti dumping duties. The petition is supported by Indian Plastic Ophthalmic Lenses Association, whose other members are M/s Techtran Polylenes Limited, Hyderabad, M/s Indian Ophthalmic Lenses Manufacturing Co Pvt Ltd, Karnataka and M/s Prakash Plastic Industries (Madras) Pvt Ltd., Chennai

1 **Product involved:** The product involved in the present petition is Plastic Ophthalmic Lenses (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from the subject countries and classified under Chapter 90 of the Custom Tariff Act (Custom Head 9001 50) Plastic Ophthalmic Lenses are used in spectacles to correct eye vision of human beings. These lenses are in finished, uncut form, ready to mount in spectacle frames. The lenses are made out of Bis Allyl Di-carbonate, generically known as CR-39 with Refractive Index of 1.498 and Abbe number of 50 plus.

The product is manufactured by M/s Techtran Polylenes Limited, Hyderabad, M/s Indian Ophthalmic Lenses Manufacturing Co. Pvt Ltd, Karnataka and M/s Prakash Plastic Industries (Madras) Pvt. Ltd., Chennai.

The present investigation covers all types of Plastic Ophthalmic Lenses. The classification, is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation

2 **Domestic Industry Standing** The petition has been filed by M/s Techtran Polylenes Limited, Hyderabad. M/s Indian Plastic Ophthalmic Lenses Association (IPOLA), Karnataka comprising of M/s Techtran Polylenes Limited, Hyderabad, M/s Indian Ophthalmic Lenses Manufacturing Co. Pvt. Ltd, Karnataka and M/s Prakash Plastic Industries (Madras)

Pvt. Ltd., Chennai have supported the petition. The petitioner, therefore, satisfies the standing to file petition on behalf of the Domestic Industry as per Rule 5 (3) (a) and (b) and also represents the domestic industry as per Rule 2(b) of Anti Dumping Rules.

3. **Country(ies) involved:** The countries involved in present investigation is People's Republic of China and Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject countries).

4. **Like Articles:** The petitioner has claimed that goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from the subject countries as they are substitutable with the domestic goods and are being used interchangeably. Accordingly, goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules 2(d).

5. **Normal Value:** The petitioners have claimed Normal Value for China PR and Chinese Taipei based on the basis of cost of production data of the subject goods appropriately adjusted which has been considered by the Authority as a prima facie evidence for Normal Value of subject goods in PR China and Chinese Taipei in accordance with the Anti-Dumping Rules as amended.

6. **Export Price:** The petitioner has provided the CIF prices in China PR and Chinese Taipei for the period 1999-2000, 2000-2001 and I.4.2001 to 31.12.2002 on the basis of statistics published by Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) and secondary source evidencing Custom's data. The Authority has determined the ex-factory price on the basis of the export price as evidenced by the petitioner and adjusted appropriately with adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight and port expenses to arrive at the ex-factory export price.

7. **Dumping Margin:** The petitioner has submitted that there is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject goods is higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

8. **Injury and Causal Link:** The Authority notes that the increase in alleged dumped imports in absolute terms from subject countries and price undercutting by the subject goods exported from the subject countries have prevented the petitioner to increase its market share, thereby prima-facie indicating that domestic industry has suffered material injury on account of alleged dumping.

9. **Initiation of Anti-Dumping Investigation:** The Designated Authority, in view of the foregoing paragraph, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

10. **Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April, 2001 to 31<sup>st</sup> March, 2002.

11. **Submission of Information:** The exporters in the subject countries/territory and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant

information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:-

**Designated Authority**  
**Ministry of Commerce & Industry**  
**Department of Commerce**  
**Directorate General of Anti Dumping**  
**& Allied Duties**  
**Udyog Bhavan, New Delhi- 110011.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. **Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

13. **Non-confidential summary:** All interested parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2). This information will be subject to acceptance in terms of Rules 7(1) and 7(2)

14. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

15. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L V SAPTHARISHI, Designated Authority



